

## भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण का मुद्दा

### प्रलिस के लिये:

वैट, उत्पाद शुल्क, कच्चे तेल की कीमतें

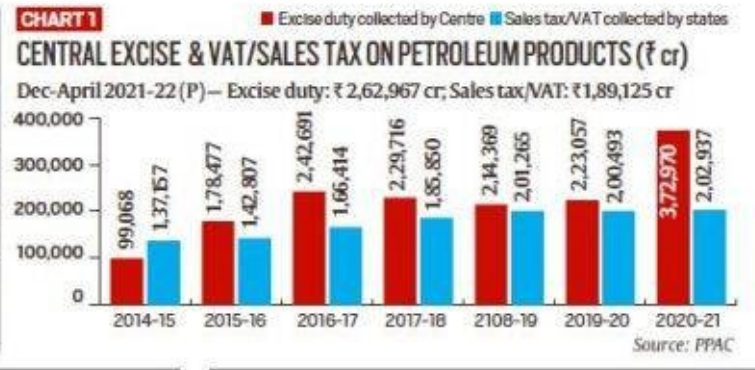
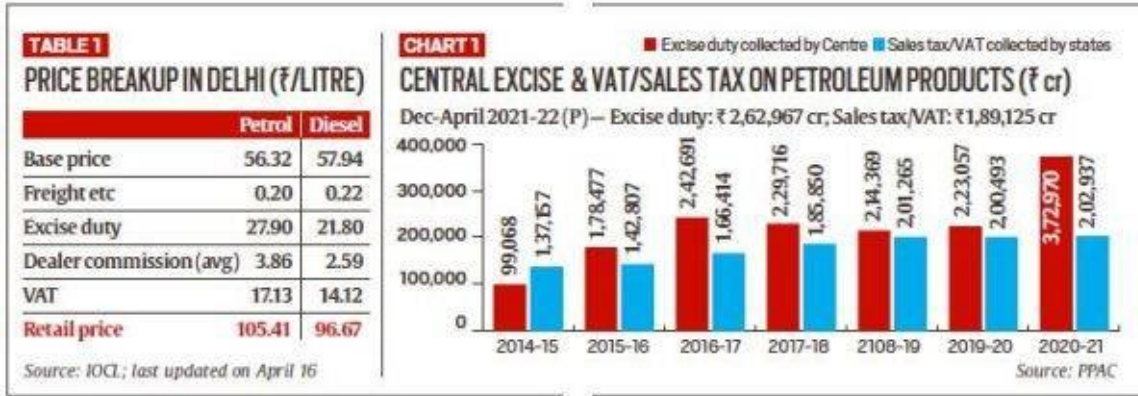
### मेन्स के लिये:

भारत में पेट्रोल और डीजल मूल्य निर्धारण का मुद्दा, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका परभाव

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई वपिकष शासति राज्यों से नागरिकों पर आर्थिक बोझ को कम करने तथा सहकारी संघवाद की भावना का पालन करते हुए इस वैश्विक संकट के समय में एक टीम के रूप में कार्य कर पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती का आग्रह किया गया है।

- महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा झारखंड राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्द्धति कर (Value-added tax- VAT) को कम नहीं किया गया है।
- वैट, उपभोग कर है जिससे आपूर्ति शृंखला के उत्पादन में शामिल हर बट्टि पर जोड़ा जाता है।



### परमुख बट्टि

- ईधन की खुदरा कीमतों के घटक:
- पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें मुख्य रूप से 3 घटकों से मलिकर बनी होती हैं:
  - आधार मूल्य (अंतरराष्ट्रीय तेल की लागत को दर्शाता है)
  - केंद्रीय उत्पाद शुल्क
  - राज्य कर (वैट)
- भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हसिसा केंद्रीय और राज्य कर है।
- उत्पाद शुल्क पूरे भारत में एक समान है, राज्य कर (बकिरी कर और मूल्यवर्द्धति कर) वभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए दरों के आधार पर भिन्न होते हैं।
  - ये कर उपभोक्ताओं के लिये ईधन को और भी महंगा बनाते हैं।
- केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में ग्राहकों को कुछ राहत देने के लिये पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया था।
  - उत्पाद शुल्क के रूप में पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई।
  - केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती करने के बाद भी ईधन की कीमतें स्थिर रहीं।
  - हालाँकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की ऊँची कीमतों की वजह से भारत में भी पेट्रोल और डीजल की

कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

- वैट दरों में अंतर के कारण वभिनि राज्यों के पेट्रोल और डीज़ल की कीमत अलग-अलग हैं।
  - उच्च वैट वाले राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी अधिकि कमी देखी गई।
- पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा दरें अंतरराष्ट्रीय कीमतों द्वारा नयित्तरति होती हैं क्योंकि भारत अपनी 85% तेल ज़रूरतों को पूरा करने के लयि आयात पर नरिभर है।

## ईधन की कीमतों से सरकार को राजस्व:

- ईधन पर उत्पाद शुल्क और वैट केंद्र और राज्यों के लयि राजस्व का एक महत्त्वपूरण स्रोत है।
- **बजट 2020-21** के अनुसार, ईधन पर उत्पाद शुल्क केंद्र के सकल कर राजस्व का लगभग 18.4% है।
  - पेट्रोलियम और अल्कोहल राज्यों के अपने कर राजस्व में औसतन 25-35% का योगदान करते हैं।
    - राज्यों की राजस्व प्राप्तरतियों में से केंद्रीय कर हस्तांतरण में 25-29% और स्वयं के कर राजस्व में 45-50% शामिल हैं।
- अप्रैल-दसिंबर 2021 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर करों से केंद्र को 3.10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मलिा, जसिमें उत्पाद शुल्क के रूप में 2.63 लाख करोड़ रुपए और कच्चे तेल पर उपकर के रूप में 11,661 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
  - इसी अवधर्ि में राज्य के कोष में कुल 2.07 लाख करोड़ रुपए जमा हुए, जसिमें से 1.89 लाख करोड़ रुपए वैट के माध्यम से संगृहीत हुये थे।

## ईधन कर कम करने के संदरभ में राज्यों की समस्याएँ:

- **राजस्व का प्रमुख स्रोत:**
  - पेट्रोलियम और अल्कोहल पर कर के माध्यम से राज्य अपने राजस्व का लगभग एक-तहिाई हसिसा प्राप्त करते हैं, अतः राज्य इन करों में कमी को एक बड़ी हानि के रूप देखते हैं।
- **महामारी का प्रभाव:**
  - आर्थिक मंदी और **महामारी** के कारण राज्य के खर्च में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आई थी।
    - राज्यों का समेकति राजकोषीय घाटा वतित वर्ष 2020 में **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** के 2.6% से बढ़कर वतित वर्ष 2021 में 4.7% हो गया था।

## मुद्रास्फीतिको कम करने के उपाय:

- चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिकि नरिभर है, इसलयि तैयार उत्पाद पर करों को कम करने या सब्सिडी को पुनः वतितरति करने के अलावा ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीतिको कम करने का कोई तरीका नहीं है।
- सब्सिडी राज्य के स्वामतिव वाले ईधन के खुदरा वकिरेताओं को कम कीमत पर वकिरय में सक्षम बनाती है, जबकनिजि रफिाइनरी जिन्हें सरकार से सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है, इस से नुकसान उठाना पड़ता है।
- यह देखते हुए कि उच्च ईधन की कीमतों का प्रभाव परविहन पर भी पड़ा है जसिसे अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, अतः सख्त मौद्रिक नीतिका पालन इस समस्या का सही समाधान होगा।

## आगे की राह

- भारत अपने तेल और गैस आयात के स्रोत में वविधिता लाने, रणनीतिक तेल भंडार बनाने, ऑटो फ्र्यूल के साथ इथेनॉल मशिर्ण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना पर कार्य कर रहा है।
- हालाँकि कच्चे तेल, गैस, पेट्रोल और डीज़ल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल की स्थिति में ऊर्जा की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लयि इन उपायों को को अपनाना आवश्यक है।
- सरकार द्वारा ईधन की कीमतों को बढ़ने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि उन पर करों में कटौती की जाए तथ **सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपकरमों** से कम लाभांश लयिा जाए।
- सरकार को ईधन और अन्य पेट्रो उत्पादों के नरियात को प्रतबिंधति करना चाहयि।
  - यह **रफिाइनरियों को अपने उत्पाद को घरेलू बाज़ार में बेचने के लयि मजबूर करेगा**, जसिसे उन्हें सुनश्चिति व्यापार-समानता मूल्य देने से छुटकारा मलिेगा।

## वगित वर्षों का प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक तेल कीमतों के संदरभ में "ब्रेंट क्रूड ऑयल" को अक्सर समाचारों में संदरभति कयिा जाता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? (2011)

1. यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है।
2. यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है।
3. इसमें सल्फर नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- बरेंट क्रूड ऑयल स्रोत की भौगोलिक स्थितिके आधार पर कयि गए कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में से एक है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/issue-of-petrol-and-diesel-pricing-in-india>

